



बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

ल.अं./52/एसएलबीसी/मार्च 2026/ 354



दिनांक : 25.06.2026

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय,

विषय : राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की मार्च 2026 त्रैमासांत की बैठक दिनांक 12.06.2026 का कार्यवृत्त

कृपया दिनांक 12.06.2026 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की मार्च 2026 को समाप्त तिमाही की समीक्षा बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त एवं कार्यवाही बिन्दु आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

शैलेंद्र कुमार सिंह

(शैलेंद्र कुमार सिंह)

महाप्रबंधक एवं संयोजक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0)

ह निवेद

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की मार्च 2026 तिमाही की बैठक
दिनांक 12.06.2026 का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की मार्च 2026 त्रैमासिक समीक्षा बैठक दिनांक 12.06.2026 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री लाल सिंह, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री हरि हर मिश्रा, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; श्री पंकज कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्रीमती संदीप कौर, आई.ए.एस., महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं बाह्य सहायतित महानिदेशालय, उ. प्र.; श्री अनिल कुमार सिंह, आई.ए.एस., अतिरिक्त आयुक्त एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग), सहकारिता, उ. प्र. शासन; श्रीमति सुमिता सिंह, निदेशक, कृषि सांख्यिकी, कृषि विभाग, उ.प्र., श्री सर्वेश्वर शुक्ला, नोडल अधिकारी, सीएम युवा, उद्योग विभाग, उ.प्र., श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; श्री केश्वन कस्तूरी आयरंगर, उप महाप्रबंधक, सिडबी, लखनऊ; श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा सहभागिता की गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एवं श्री सुनील पाण्डेय को बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया। बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में गठित कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों से सभा को निम्नवत अवगत कराया :

- ❖ फरवरी माह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित बैठक में प्रदेश के ऋण जमानुपात को मार्च 2026 तक 62% पहुंचाने के निर्देशों के क्रम में मार्च 2026 में प्रदेश का ऋण जमानुपात 60.54% के स्तर पर ही पहुंच पाया है। उन्होंने बैंको से अनुरोध किया कि ऋण जमानुपात को जून 2026 तक 62% तक पहुंचाने हेतु ठोस कदम उठाते हुए विशेष प्रयास करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- ❖ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Agriculture Infrastructure Fund Scheme को दिनांक 30.09.2026 तक अस्थायी रूप से बढ़ाये जाने से अवगत कराया गया। बैंको से अनुरोध किया कि Extended time का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक लोगो को योजना का लाभ प्रदान करे जिससे योजना के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यो राशि रु. 12,831 करोड़ को हासिल किया जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- ❖ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा PM SVANidhi योजना के अंतर्गत दिनांक 01.06.2026 से 30.06.2026 तक एक माह हेतु विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के दौरान जनपद स्तर पर "SVANidhi Mahotsav", नगर निकाय स्तर पर "Lok Kalyan Mela" तथा Census Town स्तर पर "SVANidhi Camps" का आयोजन किया जाना है। बैंको से अनुरोध किया कि कैम्पो में प्रतिभाग करने के साथ साथ अधिक से अधिक पात्र स्ट्रीट वैंडर्स को ऋण सुविधा प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- ❖ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दौरान डिजिटल KCC आवेदनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश से एक मोबाइल ऐप - KRISHIKA App की शुरुआत की गई है। बैंकों द्वारा अधिक से



अधिक केसीसी ऋण वितरण करने तथा शाखा एवं अन्य परिचालन स्तरों पर आवेदनों की प्रभावी निगरानी एवं ट्रेकिंग में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस ऐप को किसान ऋण पोर्टल (KRP) के साथ integrate भी किया गया है।

- ❖ वार्षिक ऋण योजना 2025-26 के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों रु 6.45 लाख करोड़ के सापेक्ष मार्च 2026 तक कुल रु 5.30 करोड़ (82.16%) की उपलब्धि दर्ज की गई है।
- ❖ एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के अंतर्गत कुल आवंटित लक्ष्य रु 3.66 करोड़ के सापेक्ष रु 3.06 करोड़ (84%) की उपलब्धि दर्ज की गई है। साथ ही कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य रु 2.43 करोड़ के सापेक्ष रु 2.02 करोड़ (83.13%) की उपलब्धि दर्ज की गई है।
- ❖ नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु रु 9.14 लाख करोड़ का PLP projection किया गया है जिसके क्रम में प्रदेश के सभी -75- अग्रणी जिला प्रबन्धको द्वारा तैयार District Credit Plan को प्रदेश स्तर पर समेकित कर वार्षिक ऋण योजना 2026-27 का विमोचन आज की बैठक में किया जाना है।
- ❖ दिनांक 27.06.2026 को MSME Day के अवसर पर विशेष अभियान चलाते हुए CM-Yuva योजना के अंतर्गत न्यूनतम 30% लक्ष्य हासिल किए जाने की अपेक्षा की गई है। उन्होंने बैंको से अनुरोध किया कि समस्त शाखाओं को योजना के अंतर्गत लंबित/ प्राप्त आवेदन पत्रों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने हेतु निर्देशित करें ताकि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री लाल सिंह, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का अभिवादन करते हुए समिति को सम्बोधित किया तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की पिछली बैठक दिनांक 19.03.2026 के बाद होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों व उपलब्धियों से समिति को निम्नवत अवगत कराया:

- ❖ भारत सरकार द्वारा किसानों के मध्य संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य संवर्धन एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु दिनांक 01.06.2026 से 30.06.2026 तक "खेत बचाओ अभियान" संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत बैंकों की प्रमुख भूमिका KCC Saturation एवं PMFBY के अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि e-KCC, Jan Samarth, Krishika App एवं अन्य डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग करते हुए KCC स्वीकृति/वितरण में तेजी लाएं तथा अधिकाधिक किसानों को फसल बीमा योजना से आच्छादित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- ❖ भारत सरकार द्वारा MSME एवं Airline क्षेत्र को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु ECLGS 5.0 लागू की गई है। योजना के अंतर्गत MSME इकाइयों को FY 2025-26 की चौथी तिमाही के अधिकतम कार्यशील पूंजी उपयोग का 20% तक, अधिकतम रु 100 करोड़ का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तथा इस पर NCGTC द्वारा गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा। योजना मार्च 2027 अथवा रु 2.55 लाख करोड़ की कुल गारंटी सीमा पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि JanSamarth Portal का अधिकतम उपयोग करते हुए पात्र MSME इकाइयों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराएं।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- ❖ वित्तीय वर्ष 2025-26 की मार्च तिमाही के अंत में प्रदेश का कुल बैंकिंग व्यवसाय रु 34.42 लाख करोड़ पहुंच गया है। बैंकों ने कुल जमा एवं अग्रिम में क्रमशः 10.70% एवं 13.54% की Y-o-Y Growth की है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि क्षेत्र एवं एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत ऋण में क्रमशः 16.71%, 5.11% एवं 21.76% की Y-o-Y Growth दर्ज की है।
- ❖ नोडल एजेंसी PFRDA द्वारा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत SLBC (UP) को गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु "Award of Excellence Leadership" से सम्मानित किया गया है जिसके लिए सभी बैंकर्स को बधाई दी।



- ❖ PFRDA द्वारा प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 18.47 लाख enrollment का लक्ष्य प्रदान किया गया है। उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि आवंटित लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु समस्त शाखाओं को निर्देशित करें।
- ❖ सरकारी योजनाओं यथा CM YUVA, ODOP, PM SVANidhi, PM SURYA Ghar, PM Vishwakarma, DAY NULM, R-SETI Credit Linkage, SHG Credit Linkage एवं CGTMSE के अंतर्गत और सुधार किए जाने हेतु सभी बैंकों, विशेषकर निजी बैंकों एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों से अनुरोध किया।

अपने संबोधन के अंत में उन्होंने सभा में उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए सार्थक चर्चा हेतु अपनी शुभकामनाएँ दी।

श्री हरी हर मिश्रा, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने संबोधन में वित्तीय समावेशन, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को सुदृढ़ बनाने के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष बल दिया—

- ❖ उन्होंने वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी सदस्य बैंकों को निर्देशित किया कि योजनाओं के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास किए जाएं तथा पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।
- ❖ उन्होंने वित्त मंत्रालय एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा विकसित समर्पित डिजिटल पोर्टलों (Dedicated Portals) का अधिकाधिक उपयोग करने पर बल दिया, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं प्रभावी बन सके।
- ❖ उन्होंने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों एवं पश्चिम एशिया (West Asia) में उत्पन्न अस्थिरता के दृष्टिगत आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS 5.0) के अंतर्गत पात्र उधारकर्ताओं को अधिकतम लाभ उपलब्ध कराने तथा योजना के अंतर्गत शेष पात्र मामलों को शीघ्रता से कवर करने के लिए बैंकों को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
- ❖ उन्होंने निर्देशित किया कि केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं, विशेषकर प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY), सामाजिक सुरक्षा योजना (SSS), अटल पेंशन योजना (APY) तथा विभिन्न ऋण योजनाओं में महिला लाभार्थियों की भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया जाए तथा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाए।
- ❖ उन्होंने साइबर धोखाधड़ी (Cyber Fraud) एवं साइबर अपराध (Cyber Crime) की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी बैंकों को प्रभावी रोकथाम, ग्राहकों में जागरूकता तथा मजबूत सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि साइबर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों एवं अन्य बैंकिंग शिकायतों के निस्तारण में विशेष संवेदनशीलता एवं तत्परता बरती जाए तथा शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
- ❖ उन्होंने निर्देशित किया कि जिन बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों (Unbanked Rural Centres - URCs) में अभी तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें बैंकिंग आउटलेट्स के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर कवर किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को और सुदृढ़ किया जा सके।
- ❖ उन्होंने महिला-केंद्रित योजनाओं एवं उत्पादों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर बल देते हुए कहा कि बैंक महिलाओं के लिए उपलब्ध विशेष योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाएं तथा अधिकाधिक पात्र महिलाओं को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान संचालित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

श्री पंकज कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में निम्न बिंदुओं से अवगत कराया :

- ❖ उत्तर प्रदेश देश की तीव्र गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र के लिए ऋण विस्तार की पर्याप्त संभावनाएँ उपलब्ध हैं।



❖ उन्होंने अवगत कराया कि राज्य का क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) अनुपात पूर्व वर्ष की तुलना में बेहतर हुआ है, तथापि जिन जनपदों में CD अनुपात 40% से कम है वहाँ सदस्य बैंक विशेष प्रयास करें तथा बड़े ऋणों के जिला-वार उचित लेखांकन की व्यवस्था पर भी विचार करें। साथ ही, एनपीए में कमी आने के बावजूद लंबित आरसी एवं कब्जा प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु जिला प्रशासन एवं बैंकों के मध्य समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

❖ उन्होंने वार्षिक ऋण योजना (ACP) 2025-26 की समीक्षा करते हुए कहा कि कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को और गति देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित एमएसएमई लक्ष्यों की प्राप्ति, कृषि मूल्य श्रृंखला, एफपीओ, कृषि अवसंरचना तथा सरकारी प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण बढ़ाने हेतु सभी बैंक सक्रिय प्रयास करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ KYC due खातों में Re-KYC किए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाये जाने हेतु बैंकों से आहवाहन किया। मई 2026 तक प्रदेश में लगभग 2.49 करोड़ खातों में KYC अद्यतन किया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 53.85% उपलब्धि दर्शाता है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ उन्होंने आरसेटीआई (RSETI) के लंबित प्रशिक्षण व्यय के दावों के शीघ्र निस्तारण तथा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की ऋण-संबद्धता एवं स्वरोजगार स्थापना में वृद्धि हेतु लीड बैंकों द्वारा नियमित अनुश्रवण किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ क्षेत्रीय निदेशक ने राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025-30 के अंतर्गत निर्धारित कार्य बिंदुओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए कहा कि प्रत्येक राजस्व केंद्र पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, महिला बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट्स की संख्या बढ़ाना तथा कौशल विकास योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराना प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ अंत में उन्होंने सभी सदस्य बैंकों एवं एसएलबीसी से अनुरोध किया कि लीड बैंक योजना (LBS) के प्रावधानों के अनुसार एसएलबीसी बैठकों का आयोजन प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए तथा सभी निर्णयों एवं कार्ययोजनाओं का समयबद्ध अनुपालन किया जाए।

श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, लखनऊ ने अपने संबोधन में बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए सदन को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया:

❖ फसली ऋण (Crop Loan) की सीमांत वृद्धि चिंता का विषय है। प्रदेश के कृषि ऋण लक्ष्यों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित कृषि लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित किए जाने तथा फसली ऋण वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किए जाने पर बल दिये जाने की आवश्यकता है।

❖ कम ऋण जमानुपात वाले जनपदों में सुधार किए जाने हेतु निर्देशित किया। 60% से कम ऋण जमानुपात वाले जनपदों पर विशेष ध्यान देने तथा 40% से कम ऋण जमानुपात लेकिन 100% से अधिक वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत उपलब्धि वाले जनपदों के वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों की पुनर्समीक्षा करने का सुझाव दिया गया। ऋण जमानुपात का मूल्यांकन अन्य संकेतकों के साथ भी किए जाने पर बल दिया गया।

❖ आकांक्षी जनपदों में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करने तथा विशेष रूप से बलरामपुर जनपद पर ध्यान केंद्रित करने हेतु निर्देशित किया।

❖ 'खेत बचाओ अभियान' के अंतर्गत अग्रणी जिला प्रबंधक एवं बैंकों को केसीसी संतृप्तीकरण, फसल बीमा योजना एवं संबंधित गतिविधियों में सक्रिय समन्वय करने हेतु निर्देशित किया। ऐसे जनपद, जिनमें केसीसी शिविरों की संख्या कम है, उनकी सूची कृषि विभाग द्वारा नाबार्ड को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया।

❖ वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (CFLs) का उपयोग किसानों तक पहुँच बढ़ाने तथा फसल बीमा एवं केसीसी संतृप्तीकरण हेतु प्रभावी रूप से करने पर बल दिया गया।



- ❖ दिनांक 14 मई 2026 को नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित बैठक में चर्चा किए गए विषयों, जैसे बीएलबीसी सुदृढीकरण, फसल बीमा ऑप्ट-आउट, FPO Rating Tool एवं FPO हेतु उपलब्ध क्रेडिट गारंटी आदि के संबंध में जारी कार्यबिंदुओं पर सभी हितधारकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया।
- ❖ बैंक शाखा-ग्राम मैपिंग (Branch-Village Mapping) का कार्य जिला स्तर पर शीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- ❖ कृषि सावधि ऋण (Agri Term Lending) बढ़ाने हेतु नाबार्ड द्वारा तैयार की जा रही फसलवार निवेश आवश्यकता आंकलन रिपोर्ट को PLP में शामिल करने तथा इस विषय पर अग्रणी जिला प्रबन्धको एवं विभागों के साथ विचार-विमर्श करने की जानकारी दी गई।
- ❖ प्रदेश हेतु निर्धारित स्केल ऑफ फाइनेंस का केसीसी ऋण वितरण में अनुपालन सुनिश्चित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर DLTC की स्वीकृति से अधिकतम 10% तक संशोधन किए जाने की व्यवस्था से अवगत कराया।
- ❖ एसएलबीसी वेबसाइट एवं नाबार्ड ENSURE पोर्टल के बीच API एकीकरण स्थापित करने का सुझाव दिया, जिससे हितधारकों को आवश्यक डेटा एवं विश्लेषण आसानी से उपलब्ध हो सके।
- ❖ दुग्ध किसानों के बीच बैंकिंग पहुँच बढ़ाने हेतु प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों से चयनित 200 से अधिक बैंक मित्रों की सूची सहकारिता विभाग एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के साथ साझा किए जाने का सुझाव दिया गया। साथ ही एफपीओ के ऋण संबंधी मामलों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने तथा नाबार्ड द्वारा विकसित एफपीओ क्रेडिट मूल्यांकन उपकरण एवं क्रेडिट गारंटी योजना पर प्रस्तुतीकरण आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
- ❖ नाबार्ड द्वारा तैयार जनपद / ब्लॉक स्तरीय कृषि ऋण विश्लेषण रिपोर्ट को डीसीसी/डीएलआरसी बैठकों में प्रस्तुत करने तथा बीएलबीसी बैठकों में चर्चा हेतु शामिल किए जाने का सुझाव दिया गया।

श्रीमती संदीप कौर, आई.ए.एस., महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं बाह्य सहायतित महानिदेशालय, उ. प्र.; ने अपने सम्बोधन में सभा के समक्ष निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :

- ❖ माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षानुसार प्रदेश का ऋण जमानुपात मार्च 2026 में 62% पहुंचाये जाने के सापेक्ष 60.54% पहुंचने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2026-27 में ऋण जमानुपात का स्तर 67% तक पहुंचाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए सभी सदस्य बैंकों से लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रभावी रणनीति अपनाने का आग्रह किया।
- ❖ उन्होंने निर्देशित किया कि जिन जनपदों में सी.डी. रेशियो 60% से कम है, उन जनपदों की विशेष निगरानी की जाए तथा जिला स्तर पर नियमित समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- ❖ उन्होंने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बैंकवार प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए तथा जिन बैंकों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम है, उनके लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध सुधार सुनिश्चित किया जाए।
- ❖ उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के सभी प्रमुख जनपदों, विशेष रूप से 40% से कम सी.डी. रेशियो वाले जनपदों में व्यापक स्तर पर ऋण मेले (Loan Melas) आयोजित किए जाएं, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जा सके तथा ऋण वितरण में वृद्धि हो।
- ❖ उन्होंने स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिला सदस्यों को अधिकाधिक बैंक ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष बल देते हुए कहा कि बैंक उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें तथा आजीविका संवर्धन हेतु ऋण प्रवाह बढ़ाएं।
- ❖ उन्होंने कहा कि आमजन को बैंक ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी एवं सुगम बनाया जाए, जिससे पात्र आवेदकों को अनावश्यक विलंब अथवा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।



- ❖ उन्होंने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना आदि) का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं से जोड़ा जाए।
- ❖ उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त बीमा दावा (Claim) प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण पर विशेष बल देते हुए कहा कि सभी बैंक दावा निस्तारण प्रक्रिया की नियमित समीक्षा करें तथा पात्र दावों का अधिकतम एवं समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

श्री अनिल कुमार सिंह, आई.ए.एस., अतिरिक्त आयुक्त एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग), सहकारिता, उ. प्र. शासन; ने अपने सम्बोधन में सभा के समक्ष निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :

- ❖ उन्होंने कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund - AIF) योजना की प्रगति से अवगत करते हुए कहा कि योजना की विस्तारित अवधि (Extended Period) का पूर्ण उपयोग करते हुए शेष लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित की जाए तथा पात्र परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति एवं वित्तपोषण प्रदान किया जाए।
- ❖ उन्होंने सभी सदस्य बैंकों को निर्देशित किया कि AIF योजना के अंतर्गत स्वीकृति (Sanction) एवं वितरण (Disbursement) स्तर पर लंबित सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
- ❖ उन्होंने निर्देश दिया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM) तथा अन्य पात्र योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त सभी पात्र आवेदनों को, जहां लागू हो, कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के अंतर्गत भी कवर करने की संभावना का परीक्षण किया जाए तथा पात्र मामलों को AIF के अंतर्गत परिवर्तित (Conversion) कर अधिकतम लाभ प्रदान किया जाए।
- ❖ उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि AIF योजना के अंतर्गत वित्तपोषित सभी खातों/परियोजनाओं की जियो-टैगिंग (Geo-tagging) निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए, जिससे परियोजनाओं की निगरानी एवं सत्यापन प्रभावी ढंग से किया जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति :

- ✓ दिसंबर 2026 त्रैमास की बैठक दिनांक 19.03.2026 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त सभी सदस्यों को एस.एल.बी.सी. के पत्रांक ल.अं./52/एस.एल.बी.सी./दिसंबर 2025/180 दिनांक 08.04.2026 के माध्यम से प्रेषित किये गये थे, जिसकी पुष्टि समिति द्वारा की गयी।
- ✓ सर्वप्रथम गत एसएलबीसी की बैठक के दौरान उभरे कार्यवाही बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई एवं शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित विभागों से अनुरोध किया गया।
- ✓ बैंकिंग संबंधी महत्वपूर्ण संकेतको यथा जमा, अग्रिम, ऋण जमानुपात, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि एवं एमएसएमई के अंतर्गत अग्रिम इत्यादि से अवगत कराया गया।
- ✓ प्रस्तुति के माध्यम से अवगत कराया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार एस.एल.बी.सी. की मार्च 2026 त्रैमास की बैठक का आयोजन विशेष रूप से वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता पर किया जा रहा है।
- ✓ बैठक के दौरान वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता से संबंधित निम्न एजेंडा बिन्दुओं पर पी.पी.टी. के माध्यम से चर्चा की गई :

1) मात्रात्मक मापदण्ड (Quantitative Parameter)

A. अभिगम (Access)

a) भौतिक अभिगम संकेतक



- b) डिजिटल अभिगम संकेतक
- c) प्रत्येक गाँव के 5 किमी की परिधि में बैंकिंग सेवाओं की स्थिति

B. उपयोग (Usage)

- a) बचत खाता संकेतक
 - b) बुनियादी वित्तीय सेवाओं प्रदान करना
 - c) क्रेडिट संकेतक
 - d) ऋण जमा अनुपात
- 2) गुणात्मक मापदण्ड (Qualitative Parameter)
- a) वित्तीय साक्षरता संकेतक
 - b) कौशल विकास पहल
- 3) वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को सक्षम करना
- a) भौतिक बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता
 - b) डिजिटल अवसंरचना
- 4) प्रदेश के चिन्हित जनपदों में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढीकरण की समीक्षा
- 5) वित्तीय समावेशन / वित्तीय साक्षरता / डिजिटल भुगतान से संबंधित कोई अन्य विशिष्ट मुद्दा

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- ✓ आरसी पोर्टल पर बकाया वसूली हेतु लंबित खातों की संख्या एवं धनराशि मार्च 2025 के स्तर 10.70 खाते (₹ 20,044 करोड़) से घटकर मार्च 2026 में 9.33 खाते (₹ 17,856 करोड़) रह गई है। सरफेसी खातों की संख्या एवं धनराशि मार्च 2025 के स्तर 4,833 खाते (₹ 1,706 करोड़) से मार्च 2026 में 4,497 खाते (₹ 2,003 करोड़) रही है। सभी संबंधित विभागों से बैंकों को बकाया वसूली हेतु लंबित खातों के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक सहयोग करने हेतु अनुरोध किया गया।
- ✓ वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 New Unbanked Villages की सूची प्रेषित की गई जिसमें ग्राम किलौहा, महोबा (केनरा बैंक) मे 22.10.2025 को तथा ग्राम रानाहोर, सोनभद्र (इंडियन ओवरसीज बैंक) मे 31.12.2025 को शाखा खोली जा चुकी है। ऊंचाडीह, चित्रकूट (बैंक ऑफ बड़ौदा) तथा अकथौहा, महोबा (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) मे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंकिंग आउटलेट कार्यरत है जिसके संबंध में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को अवगत कराया सूचित किया जा चुका है। ग्राम मड़ैया, चित्रकूट (भारतीय स्टेट बैंक) में स्थान चयनित किया जा चुका है तथा सितम्बर 2026 तक भवन निर्माण कर शाखा का संचालन प्रस्तावित है। उक्त केंद्र के अतिरिक्त वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2 New Unbanked Villages की सूची प्रेषित की गई जिसमें ग्राम बंदवा, सरीला, हमीरपुर (आईसीआईसीआई बैंक) तथा ग्राम मझगावन, कोरवा, प्रयागराज (एक्सिस बैंक) को ब्रिक एवं मोटर शाखा खोलने हेतु आवंटित किया जा चुका है। संबंधित बैंकों से अनुरोध है की उक्त केंद्र पर अतिशीघ्र शाखा खोलने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: संबंधित बैंक)

- ✓ राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025-30 के अंतर्गत निर्धारित कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। अवगत कराया गया कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रदेश के सभी **58,495 Unbanked Rural Centres (URCs)** को चरणबद्ध रूप से बैंकिंग आउटलेट्स से आच्छादित किया जाना है। इनमें से 22,945 केन्द्रों को पूर्व में ही बैंकिंग सुविधाओं से आच्छादित किया जा चुका है, जबकि शेष 35,550 केन्द्रों को दिसंबर, 2030 तक कवर किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में दिसंबर, 2026 तक **5,372 URCs** को बैंकिंग आउटलेट्स के माध्यम से आच्छादित किए जाने हेतु विभिन्न सदस्य बैंकों को बैंकवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं।



सभा में सभी सदस्य बैंकों से अपेक्षा की गई कि आवंटित URCS में बैंकिंग आउटलेट/बैंक मित्र/उपयुक्त बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करें तथा प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक पखवाड़े SLBC को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Women Business Correspondents - Women BCs की संख्या बढ़ाए जाने के संबंध में चर्चा की गई। अवगत कराया गया कि दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कुल बैंकिंग संवाददाताओं में महिला BCs की भागीदारी लगभग **15 प्रतिशत** है। इस संबंध में सभी सदस्य बैंकों को निर्देशित किया गया कि भविष्य में नियुक्त किए जाने वाले नए बैंकिंग संवाददाताओं में **न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला BCs** को प्राथमिकता प्रदान की जाए। साथ ही बैंक वर्षवार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार दिसंबर, 2026 तक 20 प्रतिशत, दिसंबर, 2027 तक 25 प्रतिशत तथा दिसंबर, 2028 तक 30 प्रतिशत महिला BCs सुनिश्चित करने हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन करें।

(कार्यवाही - समस्त सदस्य बैंक)

- ✓ सभा में **वार्षिक ऋण योजना) Annual Credit Plan - ACP) 2026-27** पर चर्चा करते हुए अवगत कराया गया कि राज्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत **₹8.01 लाख करोड़** का ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। सभी सदस्य बैंकों से अपेक्षा की गई कि कृषि, एमएसएमई एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ऋण प्रवाह सुनिश्चित करते हुए त्रैमासिक एवं वार्षिक लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाकर उसका अनुश्रवण करें।

(कार्यवाही - समस्त सदस्य बैंक)

- ✓ सभा में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETIs) की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान ग्रामीण गरीबों के प्रशिक्षण से संबंधित BPL दावों के प्रतिपूर्ति प्रकरणों में लंबित राशि पर चिंता व्यक्त की गई तथा संबंधित विभाग से लंबित दावों के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित करने का अनुरोध किया गया। साथ ही, जिन जनपदों में RSETI हेतु वैकल्पिक भूमि आवंटन लंबित है, वहां जिला प्रशासन एवं संबंधित प्रायोजक बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा संस्थानों के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही: यूपीएसआरएलएम, उप्र.)

- ✓ सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं यथा ECLGS 5.0 NRLM-SHG, PMFME, PM SVANidhi, PM Surya Ghar, PM Vishwakarma, AIF, ODOP, MYSY इत्यादि में अधिक से अधिक ऋण वितरण किए जाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

श्रीमति सुमिता सिंह, निदेशक, कृषि सांख्यिकी, कृषि विभाग, उ.प्र., ने चर्चा के दौरान अपने सम्बोधन में सभी बताया कि खरीफ 2026 मौसम हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एवं किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए सभा के समक्ष निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला—

- ❖ उन्होंने अवगत कराया कि भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में खरीफ 2026 मौसम हेतु प्रदेश में वर्तमान अनुबंध (Existing Contract) के अंतर्गत चयनित बीमा कंपनियों को ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकृत किया गया है।
- ❖ उन्होंने बताया कि खरीफ 2026 मौसम हेतु NCIP (National Crop Insurance Portal) पर डिजिटाइजेशन का कार्य राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होते ही पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके उपरांत बैंकों द्वारा पोर्टल पर फसल बीमा प्रस्तावों की प्रविष्टि (Insurance Entry) प्रारंभ किया जा सकेगी।
- ❖ उन्होंने आगामी मौसम में एल-नीनो (El Niño) की संभावित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी पात्र कृषकों का अधिकतम बीमा कवरेज सुनिश्चित किया जाए, जिससे प्राकृतिक जोखिमों से किसानों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा सके।



(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- ❖ उन्होंने वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS), भारत सरकार से अनुरोध किया कि कृषि ऋण पोर्टल (Krishi Rin Portal) पर कृषि सांख्यिकी विभाग को आवश्यक प्रशासनिक एवं परिचालन अधिकार (Administrative Rights) उपलब्ध कराने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक स्तर पर समन्वय एवं अनुश्रवण (Pursue) किया जाए, जिससे पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का प्रभावी उपयोग एवं निगरानी की जा सके।
- ❖ उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रदेश के सभी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी करने की प्रगति की रियल-टाइम (Real-time) निगरानी हेतु एक समर्पित पोर्टल विकसित किया जाए, जिससे योजना की प्रगति का बैंकवार एवं जनपदवार अनुश्रवण अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके।

(कार्यवाही: वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS), भारत सरकार)

श्री सर्वेश्वर शुक्ला, नोडल अधिकारी, सीएम युवा, उद्योग विभाग, उ.प्र. ने चर्चा के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) की प्रगति की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला—

- ❖ उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत बैंकों द्वारा दर्ज की गई उल्लेखनीय उपलब्धि हेतु सभी सदस्य बैंकों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी।
- ❖ उन्होंने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना के अंतर्गत 1.50 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त लक्ष्य को दिसंबर, 2026 तक प्राप्त करने हेतु विशेष अभियान चलाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- ❖ उन्होंने सभी सदस्य बैंकों से आग्रह किया कि CM-YUVA योजना के अंतर्गत लंबित सभी आवेदनों की तत्काल समीक्षा की जाए तथा पात्र आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित किया जाए।
- ❖ उन्होंने निर्देशित किया कि स्वीकृत (Sanctioned) एवं वितरित (Disbursed) प्रकरणों की प्रविष्टि योजना पोर्टल पर तत्काल अद्यतन की जाए, जिससे योजना की वास्तविक प्रगति का सही परिलक्षण सुनिश्चित हो सके।
- ❖ उन्होंने यह भी कहा कि मार्जिन मनी (Margin Money), ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) तथा CGTMSE दावों से संबंधित सभी कार्यवाहियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण की जाएं, ताकि लाभार्थियों को योजना का पूर्ण लाभ समय पर प्राप्त हो सके।
- ❖ उन्होंने निर्देश दिया कि शाखा स्तर पर लंबित आवेदनों की दैनिक निगरानी तथा क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो तथा योजना के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

बैठक के अंत में विशेष अजेंडा बिन्दु चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि CGTMSE गारंटी कवरेज सीमा पूर्णतः उपयोग हो जाने तथा बैंक के विलय (Merger) के उपरांत अतिरिक्त गारंटी सीमा उपलब्ध न होने के कारण मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) सहित AIF, PMFME, PM Vishwakarma एवं अन्य क्रेडिट गारंटी आधारित योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण प्रभावित हो रहा है। बैंक ने बताया कि MSME क्षेत्र में एनपीए में निरंतर सुधार के बावजूद गारंटी सीमा में वृद्धि न होने से बड़ी संख्या में पात्र ऋण प्रकरण लंबित हैं।

उक्त विषय पर राज्य सरकार एवं SLBC के माध्यम से भी CGTMSE के समक्ष विगत तथा वर्तमान वित्त वर्ष में गारंटी सीमा में वृद्धि करने के लिए निरंतर अनुरोध किया जा रहा है। साथ ही, इस पर विस्तृत चर्चा के उपरांत निर्णय लिया गया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS), भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए, MSME क्षेत्र में बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए, CGTMSE गारंटी कवरेज सीमा में वृद्धि हेतु आवश्यक हस्तक्षेप किया जाए, जिससे राज्य सरकार की महत्वकांशी योजना CM YUVA, विभिन्न स्वरोजगार एवं MSME योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।



(कार्यवाही: उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक)

श्री राजेश कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम ने अवगत कराया कि साइबर हेल्पलाइन 1930 के अंतर्गत संचालित Cyber Fraud Mitigation Centre (CFMC) में त्वरित कार्रवाई हेतु तैनात बैंक प्रतिनिधियों को CBS एक्सेस एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कुछ बैंकों के प्रतिनिधियों को अभी तक CBS एक्सेस उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों को लैपटॉप भी उपलब्ध नहीं हैं, जिससे साइबर धोखाधड़ी के मामलों के त्वरित निस्तारण में कठिनाई हो रही है। उन्होंने सभी संबंधित सदस्य बैंकों से शीघ्र आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हुए CFMC के प्रभावी संचालन में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त संबन्धित सदस्य बैंक)

अंत में बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।



राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, लखनऊ

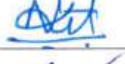
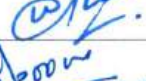
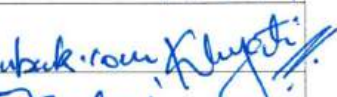
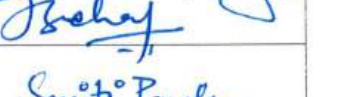
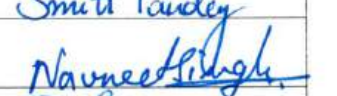
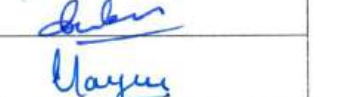
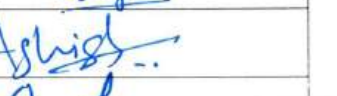
SLBC Meeting 12.06.2026

Participation Sheet

S.no.	Name of Participant	Designation	Name of Organization/ Deptt.	Contact No.	Email id	Signature
1.						
2.						
3.						
4.	Anil Kr. Singh	Adl. Registrar Bauaj, Cooperatives	Cooperatives	9793987200		
5.	Sadhana Sivasankar	Director	IF & EA	9936863788		
6.	Simila Singh	Director Secy	Krishi Dept	6307104985		
7.	Sarveshwar Shukla	Nodal officer CM-YUKA	MSME	9415054007	cmmyura@gmail.com	
8.	Anil Kr. Singh	Special Secretary	Planning Smt. of U.P.	9454412530		
9.	Bikram Bhazat Raj Singh	Investigator	NCSC	8299549039		
10.	Manisha Verma	J. Investigator	NCSC	8959686833		
11.	Anvind Misra	S.P., E.O.W Lucknow	E.O.W.	9454400322		
12.	Rajesh Kumar Yadav	SP Cyber/CKO	Cyber Crime -	9454400581		
13.	Pranav Kumar	JDA(Stats)	Agri Deptt., UP	9667504672	AgriStatUP@gmail.com	
14.	Prachi Mishra	SPM	UPSRM	9001708908	prachi.mishra.2001@gmail.com	
15.	Sudha Devi Shukla	J.M.D.	UPSRM	7007592938		
16.	Rashmiendra Kr Saxena	SDR-UP.	MORD.	7225055262	SdrLucknowSaxena@gmail.com	
17.	Rajeev Tyagi	DYCEO	UPKVIB	8383085208	ceoUPKVIB@gmail.com	
18.	JC Talukdar	Asstt. Director	KVIC, Lucknow	7641921627	KVIC.Lko2011@gmail.com	
19.	Dr. Kamal K. Singh	SMM	SUDA	9151999025	mukamup@gmail.com	
20.	A. P. Singh	C.D.D. D	Milk Commissioner offc.	9415289760	ap.singh.lko@gmail.com	

S.no.	Name of Participants	Designation	Name of Organization/ Deptt.	Contact No.	Email id	Signature
21.	Shailendra Kumar Verma	Dy DDO	Devg Dev. LKO	8318642148	vermash.203@gmail.	
22.	DR. KESHAV KUMAR	JOINT DIRECTOR	A.H. DEPT. U.P.	9415234589	drkkeshe@yaho.co.in	
23.	GAURAV SAH	Sr Vice President	HDFC	7087077770	gaurav.sah@hdfc.bank.in	
24.	SACHIN SRIVASTAVA	DVP	HDFC Bank	9359123678	sachin.kumar.srivastava@hdfc.bank.in	
25.	Smriti Tandon	AVP	Aris Bank Ltd.	9453033224	smriti.tandon@axis.bank.in	
26.	Amrit Goyal	Zonal Manager	Bank of Maharashtra	9893003610	zmlucknow@boi.bank.in	
27.	Manoj Kumar	Zonal Head	IDBI Bank	7622019904	Kumar.manoj@idbi.co.in	
28.	Harpal Singh	AGM	Central Bank of India	8553500001	agmluck20@centralbank.bank.in	
29.	Deepak Rakesh	FGM	Bank of India	9934825999	rakesh.deepak@bankofindia.bank.in	
30.	Pradeep K. Awasthi	D.G. to ZONAL HEAD	Union Bank of India	7888045921	dyzh.ludhiana@unionbank	
31.	PAUKAT ANAND	ZONAL HEAD	PUNJAB NATIONAL BANK	9819611137	PAUKAT.ANAND@PNB.CO.IN	
32.	AJIT KUMAR MISHRA	Zonal Head	Canara Bank	8570023664	Coluck@Canarabank.com	
33.	Vibhish Kumar	DDM	SBI	834960748	nmoukeshkumar@sbi.in	
34.	Kaushikendra Kumar	GM	SBI	9004961122	GK3.Khokuc@sbi.co.in	
35.	Sudhir K. Gupta	CGM	Indian Bank	9909922454	Sudhir.Gupta@indianbank.bank.in	
36.	Yadav S. Thakur	Chairman	UPGB		HO@Upgb.bank.in	
37.	Uttam K. Mishra	GM	UPGB		advances@Upgb.bank.in	
38.	K. Keshavan Iyengar	DGM	SIDBI	9935168894	keshavan@sidbi.in	
39.	नैचा बाजपैई	उमय	नाबाड	9794106221	nicha.bajpai@nabard.org	
40.	अनुराधा खोस	उमय	RBI	8090364244	anuradha@rbi.org.in	

S.no.	Name of Participants	Designation	Name of Organization/ Deptt.	Contact No.	Email id	Signature
41.	Sunil Kumar Das	GM	RBI	9434735927	sunil.kumar.das@rbi.org.in	SJS
42.	Nadhi Sivaramana	Asst. Dir	DIF	9450904563	directorgeneral@difa.gov.in	A
43.	Bablesh Kumar	ARO	DIF	9452034520	—do—	B
44.	Ashok Kumar	R.O	Planning dep.	8707808393	mprplanning@gmail.com	AMEA
45.	Aarchana Roy	Add. Dir. Coop. Officer	AIF	9792645104	aarchana.soo@coop2021@gmail.com	ARoy
46.	Ravi Kumar	BM	Kotak Mahindra Bank	7081259910	ravi.kumar5@kotak.com	Ravi
47.	Ashish Chandel	SUP	Kotak Mahindra Bank	9891490986	ashish.chandel@kotak.com	A
48.	Shashank Sengar	Nodal Officer	NPCI	9654196926	shashank.sengar@npci.org.in	mm
49.	Upendra Nath Tripathi	AGM	CGTMSE	9984886333	upendranath.tripathi@CGTMSE.in	U
50.	MONICA MALHOTRA	DGM	NATIONAL HOUSING BANK	9810515354	monica.malhotra@nhb.org.in	Monica
51.	Deepak Lefchaurya	ASO	UIDAI	9540379900	aso4-molly@uidai.net.in	DL
52.	RABEEV K. TRIPATHI	Manager	UIDAI	9717768000	ANS-ROHINI@uidai.in	R
53.	Sunil K. Bhandari	Spl. Secy	MSME	9405413488		S
54.	Atul Rajput	Regional Manager	Agro Culture Ind. Cor. of India (AIC)	9511781158	Atul.Rajput@aicofindia.com	A
55.	Manish K. Singh	Deputy Manager	AIC	7415362247	11	M
56.	Prashant Singh Rana	R.N.O.	IDFC FIRST BANK LTD.	879583924	Prashant.rana@IDFCFIRST.BANK.IN	Prana
57.	Amit Misra	R-H	INDUSIND BANK	9044412345	Amit.Misra3@Indusind.com	A
58.	Rakesh Kumar	P.A.	D G I P. U.P. Govt.	7355798084	kumardr@dgipin.com	RO
59.	Jagannath Hineni	R.O.	Board of Revenue Lucknow	8874644222	jagannathhineni@gmail.com	J
60.	Kumar Shivan	EXECUTIVE	KVIC	8739664805	Kumarshivan.in@gmail.com	K

S.no.	Name of Participants	Designation	Name of Organization/ Deptt.	Contact No.	Email id	Signature
61.	Ramanjay Singh	AGM	IOB	9140304979	37960@iob.bank.in	
62.	Ashutosh Singh	DGM	UCO Bank.	7080929394	zo.lucknow@uco.bank.in.	
63.	Aishwary Gupta	Manager	Indian Overseas Bank	9795443845	0814pccdagru@iob.bank.in	
64.	ANKKIT GUPTA	Sr. Manager	INDIAN BANK	7985180873	FGMO.LUCKNOW QINDIANBANK.BANK.IN	
65.	Sanjeev Toman	GM	UPGB	8109217351	advances ho@ upgb.bank.in	
66.	Majank Mishra	DVP	CSB Bank	9919594466	majank.mishra@ CSB.BANK.IN	
67.	Rajeev Kumar Bancel	GM	Punjab & Sind Bank	965025360	Zolucknow@psb.bank.in	
68.	Nareesh Kumar	AGM	Punjab & Sind Bank	9465633323	Zolucknow.psb.bank.in	
69.	Apoorv Kapoor +1	VP	Yes Bank	9794999220	apoorv.kapoor@ yes.bank.in	
70.	Gaurav Tiwari	Officer	The Nainital Bank Ltd	8462921642	np.lucknow@naital.bank.co.in	
71.	Khyati Srivastava	AVP	Banellah	8874096928	kh.nialanager@banellahbank.com	
72.	Tokhan Sahani	Manager	Karnataka Bank.	7838093350.	Lucknow@kankbank.com	
73.	Smriti Pandey	Asst. Manager	South Indian Bank	8299425471	bh0444@sib.co.in	
74.	NAVNEET SINGH	SENIOR MANAGER	A.U SMALL FINANCE BANK	7906963860	navneetsingh10@AUBank.in	
75.	Rajesh Kumar	VP	Ujjivan Small Finance Bank	9116113679	Rajesh.kr@UJJIVAN.in	
76.	Ankur Khandelwal	Sales in charge	IPPB	7905130059	08aipuradeshcircle @ippbonline.in	
77.	MAYURI SAXENA	Chief Manager	APBL	9935099410	MAYURI.SAXENA@AIRTEL BANK.COM	
78.	Ashish Nigam	Chief Manager	Airtel Payments Bank	9935099063	ashish1.nigam@ airtelbank.co.in	
79.	Amit Suyash	Senior Manager	FINO PAYMENTS BANK	6391486257	AMIT.SUYASH@ FINO.BANK-IN	
80.	Arman	PO	Equitas Small Finance Bank	7607852272	cman@equit2272 @cmail.com	

S.no.	Name of Participants	Designation	Name of Organization/ Deptt.	Contact No.	Email id	Signature
81.	Abhinav Kumar Singh	Assistant Commissioner	Handloom & Textiles Department. U.P.	9451133281	dhup @rediffmail .com	Abhinav
82.	Dharmendra Kumar	Sr. Manager	Central bank of India	9472343351	rdluckzo @centralbank .com	D
83.	AVINASH DWIVEDI	DGM	IDBI Bank Ltd	8851582630	avinash.dwivedi @idbi.co.in	Avinash
84.	RATHISH GUPTA	Sr. Manager	Bank of Maharashtra	9821237994	rbg@bankofmaharashtra .bank.in	R
85.	Ravendra Kumar	chf-mngt	P.N.B	9634212844	statenralc @Pnb.Bank.in	R
86.	Sanjeev Kr Singh	Sr. Manager	Bank of India	7017654085	tgmo.lucknow @bank of india .bank.in	Sanjeev
87.	Devesh Pratap Singh	Sr. Manager	Canara Bank	9455504252	msnecoluck @Canara bank .com	Devesh
88.	Divyanshu Tripathi	Manager	Canara Bank	7706991580	divyanshut @Canarabank.com	Divyanshu
89.	Ambresh Sharma	AGM	State Bank of India	7007343174	ambresh.s @sbi.co.in	Ambresh Sharma
90.	Ajay Kumar	AGM.	-DO-	9452183363	agmb.lko@icbi.co.in	Ajay
91.	D K PRASAD	DGM	UPSB	9415519922	upsb1dol @upsb.bank.in	D K
92.	ASHOK KUMAR	GM	UPSB	7525706031	UPSBIdol @UPSB.Bank.in	A
93.	Kanchan Chinnasani	Chief Manager	ICICI Bank Ltd	8853989342	kanchan.chinnasani @icici.bank.in	Kanchan
94.	राजेंद्र प्रसाद गुप्ता	राजस्व	राष्ट्रीय व्यापारी बचत को-ऑपरेटिव बैंक	9897012300 9412288831	Rajendra.gupta@rwb.co.in	Rajendra
95.	सुनील पाण्डेय	,,	,,	8840196073 9335310787	SUNIL PANDEY burms2 @.gmail.com	Sunil
96.	JAR KISHORE JATHAR	STATE RISK MANAGER	UNITY SMALL FINANCE BANK	7080210767	Jai.Patthar@unitybank .co.in	J. Jathar
97.	Manish	Deputy Manager	AIC	7415312147	manishk @aicofindia.com	Manish
98.	SNISNIK	SI	UP Police	9454407235		S
99.						
100.						